



## POCSO अधिनियम

### प्रलिस के लयि:

[POCSO अधिनियम](#), वर्ष 1992 का बाल अधकारों पर संयुक्त राष्ट्र कनवेंशन, भारतीय दंड संहति, कशिर नयाय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, POCSO नयायालय

### मेन्स के लयि:

POCSO अधिनियम, कार्यानवयन के मुद्दे और आगे की राह

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने [लोकसभा](#) को सूचति कयि है कि [यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण \(POCSO\) अधिनियम, 2012](#) बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लयि सरकार द्वारा बनाए गए महत्त्वपूर्ण कानूनों में से एक है।

### POCSO अधिनियम:

#### परचय:

- POCSO अधिनियम 14 नवंबर, 2012 को लागू हुआ, जो वर्ष [1992 में बाल अधकारों पर संयुक्त राष्ट्र कनवेंशन](#) के भारत के अनुसमर्थन के परणामस्वरूप अधिनियमति कयि गया था।
- इस वशेष कानून का उद्देश्य [बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराधों](#) को संबोधति करना है, जनिहें या तो वशेष रूप से परभाषति नहीं कयि गया या पर्याप्त रूप से दंड का प्रावधान नहीं कयि गया है।
- यह अधिनियम [18 वर्ष से कम आयु के कसी भी व्यक्तिको बच्चे के रूप में परभाषति करता है।](#) अधिनियम अपराध की गंभीरता के अनुसार सज़ा का प्रावधान करता है।
  - बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से [बच्चों के यौन शोषण के मामलों में मृत्युदंड सहति अधिक कठोर दंड का प्रावधान](#) करने की दशि में [वर्ष 2019 में अधिनियम](#) की समीक्षा तथा इसमें संशोधन कयि गया।
  - भारत सरकार ने [POCSO नयिम, 2020](#) को भी अधिसूचति कर दयि है।

#### वशेषताएँ:

- लगि-नषिपकष प्रकृति:**
  - अधिनियम के अनुसार, लड़के और लड़कयि दोनों यौन शोषण के शकार हो सकते हैं औरपीड़ति के लगि की परवाह कयि बना ऐसा दुरव्यवहार एक अपराध है।
    - यह इस सदिधांत के अनुरूप है कि [सभी बच्चों को यौन दुरव्यवहार और शोषण से सुरक्षा का अधकार है](#) तथा लगि के आधार पर कानूनों को भेदभाव नहीं करना चाहयि।
- मामलों की रिपोर्टिंग में आसानी:**
  - न केवल व्यक्तयिों द्वारा बल्कि संस्थान भी [अब नाबालगिों के साथ यौन दुरव्यवहार के मामलों की रिपोर्ट करने](#) के लयि पर्याप्त रूप से जागरूक हैं कयोंकि रिपोर्ट न करना [POCSO अधिनियम के तहत एक वशिषिट अपराध](#) बना दयि गया है। इससे बच्चों से संबधति यौन अपराधों को छपाना तुलनात्मक रूप से कठनि है।
- शर्तों की स्पष्ट परभाषा:**
  - बाल पोरनोग्राफी से संबधति सामग्री के संग्रहण को [एक नया अपराध](#) बना दयि गया है।
  - इसके अलावा 'यौन उत्पीड़न' के अपराध को [भारतीय दंड संहति](#) में 'महिला की लज्जा भंग करने' की अमूरत परभाषा के वषिरीत स्पष्ट शब्दों में (बढ़ी हुई न्यूनतम सज़ा के साथ) परभाषति कयि गया है।

#### POCSO नयिम 2020:

- अंतरमि मुआवज़ा और वशेष राहत:**
  - POCSO नयिमों का नयिम-9 [वशेष अदालत को FIR](#) दर्ज होने के बाद बच्चे के लयि राहत या पुनरवास से संबधति ज़रूरतों हेतु अंतरमि मुआवज़े का [आदेश देने की अनुमति](#) देता है। यह मुआवज़ा अंतरमि मुआवज़े (यदि कोई हो) के वरिद्ध समायोजति कयि जाता है।

- वशिष राहत का तत्काल भुगतान:
  - POCSO नयिमों के अंतर्गत बाल कल्याण समिति (CWC) ज़िला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA), ज़िला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) या फंड का उपयोग करके भोजन, कपड़े और परिवहन जैसी आवश्यक ज़रूरतों के लिये तत्काल भुगतान की सफ़ारिश कर सकती है। इसे कश्शोर न्याय अधिनयिम, 2015 के अंतर्गत बनाए रखा गया।
  - भुगतान CWC की अनुशंसा प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर कया जाना चाहयि।
- बच्चे के लयि सहायक व्यक्तऱि:
  - POCSO नयिम CWC को जाँच और परीक्षण प्रक्रयिा के दौरान बच्चे की सहायता के लयि एक सहायक व्यक्तऱि प्रदान करने का अधिकार देता है।
  - सहायता करने वाला व्यक्तऱि बच्चे के सर्वोत्तम हतऱिों को सुनश्चिति करने के लयि ज़मिमेदार है, जसिमें शारीरकि, भावनात्मक एवं मानसकि कल्याण, चकितिसा देखभाल, परामर्श तथा शकिषा तक पहुँच शामिल है। वह बच्चे एवं उसके माता-पति या अभिभावकों को मामले से संबंघति अदालती कारयवाही और वकिसा के बारे में भी सूचति करेगा।
- नोट: देश में आपराधकि कानून (संशोधन) अधिनयिम, 2018 को आगे बढ़ाते हुए न्याय वभिाग ने अक्टूबर 2019 में देश भर में कुल 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs) (389 वशिषिट POCSO अदालतों सहति) की स्थापना के लयि एक केंद्र प्रयोजति योजना प्रारंभ की है।
- 31 मई, 2023 तक देश भर के 29 राज्यों/केंद्रशासति प्रदेशों में 412 वशिषिट POCSO (e-POCSO) न्यायालयों सहति कुल 758 FTSCs कारयरत हैं।

## POCSO अधिनयिम से जुड़े मुद्दे एवं चुनौतयिाँ:

- जाँच से जुड़ा मुद्दा:
  - पुलसि बल में महिलाओं का कम प्रतनिधितिव:
    - POCSO अधिनयिम में बच्चे के नविसा या पसंद के स्थान पर एक महिला उप-नरीकषक द्वारा प्रभावति बच्चे का बयान दर्ज करने का प्रावधान है।
    - ऐसी स्थतऱि में जब पुलसि बल में महिलाओं की संखया केवल 10% है, इस प्रावधान का अनुपालन करना व्यावहारकि रूप से असंभव है, साथ ही कई पुलसि स्टेशनों में तो मुश्कलि से ही महिला कर्मचारी मौजूद हैं।
  - जाँच में कमयिाँ:
    - हालौक ऑडयिो-वीडयिो माध्यमों का उपयोग करके बयान दर्ज करने का प्रावधान है, फरि भीकुछ मामलों में जाँच एवं अपराध के परदृश्यों के संरक्षण को लेकर खामयिाँ अभी भी मौजूद हैं।
      - शफी मोहम्मद बनाम हमिाचल प्रदेश राज्य (2018) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जघिन्य अपराधों के मामलों में जाँच अधिकारी का करतव्य है कि वह अपराध स्थल की तस्वीर और वीडयिोग्राफी करे, साथ ही उसे साक्ष्य के रूप में संरक्षति करे।
    - न्यायकि मजसिट्रेटों द्वारा कोई परीक्षा नहीं:
      - अधिनयिम का एक अन्य प्रावधान न्यायकि मजसिट्रेट द्वारा अभयिोजक के बयान की रकिॉर्डगि को अनविरय करता है।
      - हालौक ऐसे बयान ज़्यादातर मामलों में दर्ज कयि जाते हैं, लेकनि न तोन्यायकि मजसिट्रेट को मुकदमे के दौरान पूछताछ के लयि बुलाया जाता है और न ही बयान से मुकरने वालों को दंडति कया जाता है। ऐसे में इस तरह के बयान खारजि हो जाते हैं।
- आयु नरिधारण का मुद्दा:
  - यदयपकिशोर अपराधी का आयु नरिधारण कश्शोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनयिम, 2015 द्वारा नरिदेशति है, कश्शोर पीडितऱिों के लयि POCSO अधिनयिम के तहत ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।
    - जरनैल सहि बनाम हरयिाणा राज्य (वर्ष 2013) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रदत्त वैधानकि प्रावधान को अपराध के शकिार हुए कसिी बच्चे के लयि उसकी आयु नरिधारति करने में भी सहयिगी आधार होना चाहयि।
    - हालौक कानून में कसिी भी बदलाव या वशिषिट नरिदेशों के अभाव में जाँच अधिकारी अभी भी स्कूल प्रवेश-त्याग रजसिट्र में दर्ज जन्मतथि पर ही भरोसा बनाए हुए हैं।
- आरोप-पत्र दाखलि करने में देरी:
  - POCSO अधिनयिम के अनुसार, अधिनयिम के तहत दर्ज मामले की जाँच अपराध होने या अपराध की रपिर्गि की तथि से एक माह की अवधकि के भीतर करना आवश्यक है।
  - हालौक व्यावहारकि रूप से पर्याप्त संसाधनों की कमी, फोरेंसकि साक्ष्य प्राप्त करने में देरी या मामले की जटलिता जैसे वभिन्नि कारणों से जाँच पूरी होने में प्रायः एक माह से अधिक का समय लगता है।
- हालयिा यौन संबंघ को साबति करने के लयि शर्त आरोपति नहीं:
  - न्यायालयों को यह वचिार करने की आवश्यकता होती है कि अभयिुकत् ने POCSO अधिनयिम के तहत अपराध कया है।
  - भारतीय साक्ष्य अधिनयिम (जहाँ अभयिोजन पक्ष को साबति करना होता है कि हाल में यौन संबंघ बना और इसमें पीडिति की सहमतऱि शामिल थी) के वपिरीत POCSO अधिनयिम अभयिोजन पक्ष पर कोई शर्त आरोपति नहीं करता है।
  - हालौक यह देखा गया है कि पीडिति/पीडिति के नाबालगि साबति होने के बाद भी न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान ऐसे कसिी अनुमान पर वचिार नहीं कया जाता है।
    - ऐसे परदृश्यों में दोषसदिधि दर में अपेक्षति वृद्धि होने की संभावना नहीं है।

## प्रमुख संबंधित पहलें

- बाल दुरव्यवहार रोकथाम और अनुवेषण इकाई
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- कश्मिर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- बाल विवाह निषिद्ध अधिनियम (वर्ष 2006)
- बाल शर्म निषिद्ध और वनियिमन अधिनियम, 2016
- विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के तहत POCSO अदालतें

## आगे की राह

- सरकार को POCSO संबंधी मामलों में **जाँच एजेंसियों को धन और कर्मियों जैसे पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने** चाहिये। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि मामले की जाँच समयबद्ध और कुशल तरीके से की जाए।
- POCSO मामलों का प्रबंधन करने वाले **जाँच अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया** जाना चाहिये। इसमें साक्ष्य एकत्र करने एवं संरक्षण करने, बाल पीड़ितों तथा गवाहों के बयान लेने और POCSO अधिनियम की कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु **उचित तकनीकों पर प्रशिक्षण प्रदान** करना शामिल हो सकता है।
- POCSO मामलों के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना से मामलों का नपिटारा त्वरित गति और कुशलता से सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। इससे सुनवाई की प्रक्रिया में तेज़ी लाने में भी मदद मिलेगी, जो पीड़ित एवं उसके परिवार के लिये महत्वपूर्ण हो सकता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. राष्ट्रीय बाल नीतिके मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिये तथा इसके कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डालिये। (2016)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/pocso-act-3>